1	2	3
7.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश वस्तु व्यापार निगम लि०
8.	तमिलनाडु	तमिलनाडु नागरिक पूर्ति निगम लि०
9.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम लि०
10.	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य नागरिक पूर्ति निगम
11.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु पूर्ति निगम
12.	गुजरात	गुजरात राज्य नागरिक पूर्ति निगम
13.	दिल्ली	नागरिक पूर्ति निगम, दिल्ली

Scheme for Promotion of Agricultural Operations in Dry Lands

*375. SHRI K. PRADHANI :

SHRI K. MALLANNA :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have framed schemes durnig the current Five Year Plan to promote agricutulral operation in dry lands;

(b) whether it is also a fact that great emphasis was laid on this issue;

(c) if so, whether Government have soguht foreign assistance in this regard; and

(d) if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) and (b) Yes, Sir,

(c) and (d) Watershed development approach has been adopted as a national strategy for development of dryland agriculture for which no large scale foreign aid is necessary. However, some technical assistance to the research programme is being given by Canada. A Pilot Project for Watershed Development in limited areas in four States is being launched with the assistance of World Bank.

Betel Research Project in West Bengal

*376. SHRI SATYAGOPAL MISRA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether his Ministry has taken any steps to set up any full-fledged Betel Research Project in West Bengal which is the largest producer State of betel leaves in the country ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) Yes, Sir. The Indian Council of Agricultural Research has sanctioned on March 21, 1983 a full-fledged Research Centre on Betelvine at the Bidhan Chandra Krishi Vishwa Vidyalaya (BCKVV) Kalyani in West Bengal which is one of the major betelvine growing States of the country.

(b) The Betelvine Research Project has 8 centres in different parts of the country

apart from a Coordinating Cell with a Tissue Culture Unit located at the Indian Institute of Horticultural Research, Bangalore. BCKVV is one of the research centres of the Project which has been sanctioned for a period of 2 years at a total cost of Rs. 3,27,580/-. The staff cost and facilities provided for BCKVV are at par with the other centres. The priority areas for research in respect of the Project are :—

(i) Diagnosis and control of major diseases and pests of *pan*.

(ii) Improvement in agro-horticultural techniques of *pan* cultivation.

(iii) Identification and conservation of *pan* varieties in the country and varietal improvement.

(vi) Research on tissue culture on *pan* for conservation of germplasm material.

(v) Any other important problems that may arise.

(c) In view of the reply at (b) above the reply to this part does not arise.

दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रयोग न किये गये कागज का रद्दी के रूप में बेचा जाना

*377. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 दिसंबर, 1982 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रयोग न किये गये कागज को रद्दी के रूप में बेच दिया गया;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का विवरण क्या है और उन्हें क्या सजा दी गई है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग द्वारा विभागीय जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारी की जिम्मेदारी ठहराई गई तथा उसे आलेख्य चेतावनी जारी की गई।

वनस्पति निर्माताओं को जारी किये गये निदेश

*378. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

श्री भीम सिंह :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति निर्माताओं को भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वनस्पति का निर्माण करने हेतु सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये निदेश कब दिये गये और उसके क्या करण हैं; और

(ग) इन निदेशों के पालन में सुविधा के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या नये कदम उठाये गये हैं ?